देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 11.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :—

- दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट; देहरादून सहित पूरे राज्य में चौक—चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुझावों के आधार पर उत्तराखंड के अगले 25 वर्षों के विकास के लिये राज्य सरकार ने कार्ययोजना बनानी शुरू की।
- उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती उपचुनाव 2025 की तिथि घोषित की; त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के बाद रिक्त हुए पदों पर बीस नवंबर को होगा मतदान।
- और, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिये तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

हाई अलर्ट

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून सहित पूरे राज्य में चौक—चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को राज्यभर में विशेष सतर्कता बरतने, सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश जारी किए हैं। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं, धार्मिक स्थलों, बाजारों, मॉल, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, गश्त और तलाशी अभियान तेज करने तथा सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में चीता मोबाइल यूनिट्स, पेट्रोल कार, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को सक्रिय कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार तलाशी और चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस महानिदेशक ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

कार्ययोजना

उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझावों को राज्य सरकार ने आगामी 25 वर्षों के विकास रोडमैप की आधारशिला मानते हुए उन पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आत्मा आध्यात्म, पर्यटन और प्राकृतिक संपदा में निहित है, और उत्तराखंड को ''विश्व की आध्यात्मिक राजधानी" के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नैचुरोपैथी संस्थान और होम स्टे को मिलाकर एक संपूर्ण पर्यटन व वेलनेस पैकेज तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वाइब्रेंट विलेज को छोटे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ स्थानीय भोजन, संस्कृति और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने राज्य के मेलों और पर्वों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ''एक जिला–एक त्यौहार'' अभियान शुरू करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर हब बनाने, ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने तथा फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पादों से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर दिया।

उत्तराखंड@25

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ''उत्तराखंड@25 : रोमांच, आध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव'' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने चमोली ज़िले के नीति क्षेत्र में आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन रेस के लोगो का अनावरण किया और पर्यटन विभाग की थ्रोन ऑफ द गॉड्स कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी प्रतियोगिता के विजेताओं, उत्कृष्ट होम स्टे संचालकों, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर तथा काला नाग चोटी का सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोहियों और आईटीबीपी के दल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों से रजत जयंती पर्व के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड ने तेज़ी से प्रगति की है, जो आंदोलनकारियों की तपस्या का परिणाम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी सहित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

श्री धामी ने कहा कि स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के माध्यम से गांव–गांव में आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई पर्यटन नीति के तहत 207 से अधिक निवेशकों की पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समन्वय और ज़िलों से संबंधित मुद्दों के समाधान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों और जनपदों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां भी समस्या है, वहां मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजने और मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा करने के लिए पहले उपलब्ध बजट का उपयोग करने के निर्देश भी दिए।

पंचायत उपचुनाव

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती उपचुनाव 2025 की तिथि घोषित कर दी है। आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2025 के बाद रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है।

इन उपचुनावों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के वे पद शामिल होंगे, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित नहीं हैं।

आयोग के अनुसार मतदान 20 नवम्बर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन पत्र आज से 13 नवम्बर तक कार्य दिवसों में भरे जा सकेंगे, जिनकी जांच 14 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। उम्मीदवार अपने नामांकन 20 नवम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वापस ले सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को उपचुनाव प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री घोषणाओं पर कार्य

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पूर्ण, गतिमान और अभी तक प्रारंभ न हो सकी घोषणाओं का अलग–अलग विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गतिमान घोषणाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट तीन दिनों में, जबकि किसी कारणवश शुरु न हो सकी घोषणाओं का विवरण सात दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं की सूची अलग से तैयार की जाए और उन्हें उच्च प्राथमिकता पर कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं को तत्काल शुरू किया जा सकता है, उनके प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं, जबकि जिनमें बाधा है, उन्हें विभागीय स्तर पर प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए।

उन्होंने सचिव एस.एन. पांडेय को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए और जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराते हुए सुधार सुनिश्चित किया जाए।

ड्रोन लाइट शो

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी–उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा एक भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया।

"मेक इन इंडिया" के तहत बने 300 से अधिक ड्रोन ने आकाश में विभिन्न आकृतियाँ बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो की शुरुआत भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा के अवतरण के दृश्य से हुई, जिसके बाद "उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष", "ॐ गैलेक्सी", "त्रिशूल और डमरू", "केदारनाथ" और "बदरीनाथ धाम" जैसे दृश्य प्रस्तुत किए गए।

ड्रोन के माध्यम से राज्य पक्षी मोनाल, पारंपरिक छोलिया नृत्य, लोक वाद्य यंत्र और कुमाऊंनी पारंपरिक वेशभूषा जैसे दृश्य भी बनाए गए, जिन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सजीव कर दिया।

यूकाडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. टोलिया ने कहा कि उत्तराखंड केवल दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि नहीं, बल्कि नवाचार और प्रगति का भी प्रतीक है। यह ड्रोन शो परंपरा और तकनीक के संगम का प्रतीक है, जो रचनात्मक पर्यटन अनुभवों के नए युग की शुरुआत करता है।

रोडमैप तैयारी

उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए प्रमुख बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड के लक्ष्यों और उनके अनुरूप रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई।

अधिकारियों ने रजत जयंती समारोह के दौरान आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन जैसे आयोजनों से मिले अनुभवों और सुझावों को साझा किया। मुख्य सचिव ने सभी सुझावों और अनुभवों का दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव, प्रोटोकॉल को सभी सुझावों की सूची बनाकर उन्हें नीति निर्माण में शामिल करने के निर्देश दिए।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

दिल्ली धमाके की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है... हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– दिल्ली में धमाका, 9 मरे, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में विस्फोट, दिल्ली–उत्तराखंड–यूपी समेत पूरे देश में हाई अलर्ट।

उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए 20 नवंबर को होंगे चुनाव, हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– राज्य निर्वाचन आयोग 11 नवंबर को जारी करेगा उपचुनाव की अधिसूचना।

उत्तराखंड के 100 स्कूलों में बनेगी एआई लैब– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– शिक्षा विभाग और बियोंड मेंटोर संस्था के मध्य हुआ समझौता।

रुद्रपुर में ट्रेडिंग के नाम पर सेवानिवृत्त शिक्षिका से 43 लाख की ठगी, दैनिक जागरण का शीर्षक– खबर के मुताबिक न्यूआमा एज कंपनी का अधिकारी बनकर ठगी को दिया अंजाम।

प्रदेश में फिर हड़ताल पर गए 22 हजार उपनल कर्मी– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– नियमितीकरण समेत अन्य लंबित मांगों पर अमल ना होने से नाराज उपनल कर्मचारियों का देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में अनिश्त कालीन धरना शुरू।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर–

- दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट; देहरादून सहित पूरे राज्य में चौक–चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुझावों के आधार पर उत्तराखंड के अगले 25 वर्षों के विकास के लिये राज्य सरकार ने कार्ययोजना बनानी शुरू की।
- उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती उपचुनाव 2025 की तिथि घोषित की; त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के बाद रिक्त हुए पदों पर बीस नवंबर को होगा मतदान।
- और, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिये तेजी से काम करने के निर्देश दिए।